[Shri Ravindra Varma]
pending for discussion and a tentative schedule of the Ministries that will come up for discussion has been circulated, the Minister of Parliamentary Affairs does not make a statement. There has, therefore, been no departure from the past precedents.

The hon. Member raised the question of the possibility of some changes in dates depending upon the availability of the hon. Ministers concerned. If there is to be any such change, the House will be notified in due course.

12.48 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) REPORTED STRIKE IN KHETRI COPPER PROJECT

श्री नाथू सिंह (दासा) अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन का ध्यान एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछले 25 फरवरी से खेतडी ताबा प्रोजेक्ट के लगभग 8 हजार मजदूर पूर्णत हडताल पर हैं जिससे वहां का उत्पादन बिल्कुल ठप्प हो गया है। मजदूरो को पिछले कई दिनों से वेतन नही मिल रहा है। होली नजदीक है। ऐसे अवसर पर मजदूरों को वेतन न मिलने से उन मे व उनके परिवार के सदस्यों मे घोर निराशा उत्पन्न हो गई है। उसमे वहा तनाव की स्थिति बनती जा रही है। कर्मचारियो के प्रतिनिधिमण्डल ने मंत्री महोदय से मिलकर हल निकालने का भी प्रयत्न किया लेकिन असफल रहे। वैसे हडताल मजदूरों द्वारा प्रारम्भ नही की गई थी बल्कि प्रबन्धकों द्वारा कराई गई थी। बात केवल रस्सा बदलने की थी। जिस रस्से के द्वारा मजदूर खान मे उतरते है उसको सेफ्टी विभाग के अधिकारियो ने जाच के दौरान ठीक नहीं समझा व प्रबधकों को उस रस्से को बदलने की सलाह दी लेकिन रस्सा नहीं बदला गया। तब मजदूरो ने अपनी जान बचाने के लिए यही उचित समझा कि बिना रस्सा बदले अर्थात् इस पुराने रस्से के सहारे नीचे खान मे नहीं उतरा जाये। जब फिर भी रस्सा न बदला गया तो मजदूरों ने नीचे जाने से इनकार कर दिया और पांच वर्ष पूर्व से चली आ रही कुछ और मांगों को साथ जोडकर मैनेजमैंट से बात करने की इच्छा प्रकट की। मगर मैनेजमैंट ने बात करने से साफ इनकार कर दिया। बस इसी से वहां हडताल प्रारम्भ हो गई। कई संसद सदस्य वहां गये। मैं स्वयं भी वहा गया। वहां के मजदूरों से बातचीत की। हडताल होने से लाखों रुपये का देश को नुकसान हो रहा है। कर्मचारी चाहते है कि वहां उन्हें यूनियन बनाने का अधिकार दिया जाये, दो वर्ष से कार्य कर रहे मजदूरों को स्थायी किया जाये, बोनस दिया जाये एवं कपडे जो कि नीचे खान मे जाने से खराब हो जाते हैं, मजदूरों को दिये जायें। अर्थात् वर्दी देने की व्यवस्था की जाय—ये सब उन मजदूरो की समस्यायें हैं।

अध्यक्ष महोदय, ये समस्यायें बहुत कठिन नही हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि देश के कर्मचारियों के हितो को ध्यान मे रखते हुए, वे उनसे बातचीत करे और उचित मागो को स्वीकार करे, तथा अन्य मार्गों पर विचार करने के लिए कोई कमेटी नियुक्त करे, ताकि हडताल समाप्त हो सके, कर्मचारियों का असन्तोष समाप्त हो और वहा पर पुन. उत्पादन प्रारम्भ हो सके।

मै मंत्री महोदय से पुन कहना चाहूंगा कि उन मजदूरों की समस्याओ पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए उन्हे यहां बुलायें या स्वयं वहां पर जायें और बातचीत करके उनकी समस्याओं का हल निकालें, ताकि देश नुकसान से बच सके और उन कर्मचारियों को कुछ दिया जा सके, जिससे उनका असन्तोष समाप्त हो।

(ii) REPORTED STRIKE BY EMPLOYEES OF MOGUL LINES CAUSING HARDSHIPS TO PASSENGERS GOING TO KONKAN.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): I rise here to raise a matter of urgent public importance in this House under Rule 377. Operation

of ships on West Coast of Konkan was done by Bombay Steam Navigation Company and by M/s. Chougule Steamship Company prior to 1973. This service was nationalised in 1973. Prior to nationalisation, ships of Bombay Steam Navigation Company used to call at 20 ports and that of Chougule Steamship used to call at 16 Ports. After nationalisation, ships are operated by Mogul Lines and since October, 1977, ships of Mogul Lines are calling on at four ports on this line. Employees of Mogul Lines are reported to have gone on strike since Monday, the 20th March, 1978. This is the peak season of the traffic of the year. The people of Konkan living in Bombay want to rush to their respective homes for Holi festival and because of the strike, considerable inconvenience will be caused to them. I, therefore, request the Minister and the Government to take immediate action in the matter to end the strike and direct Mogul Line to meet the demands of the employees and in the meantime, make alternative arrangement to operate the ships and avoid inconvenience that is being caused to passengers.

(iii) REPORTED KIDNAPPING OF TWO GIRLS OF RAMA KRISHNA PURAM, NEW DELHI.

श्री युवराज (कटिहार). अध्यक्ष महोदय, आज सारे दिल्ली शहर की जनता में बढ़ती हुई असुरक्षा की भावना व्याप्त है । यह घटना 15 मार्च की है, आर० के० पुरम गर्ल्ज हायर सैकेण्डरी स्कूल की छात्रा—नन्दिता मजूमदार और पंछी रावत, जो 9वीं क्लास में पढ़ती थीं, जब घर वापस आ रही थीं तो रास्ते में इन दोनों छात्राओं को किडनेप कर लिया गया और इन को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के गेस्ट हाउस में रखा गया । दूसरे दिन पंछी रावत घर वापस आ गई, लेकिन जब नन्दिता मजूमदार (क्रमा) चार-पांच दिन तक घर नहीं लौटी तो बिमल सरकार जो एक गवर्नमेंट-आफ़ सियल भी हैं, हमारे माननीय सदस्य श्री पूर्ण सिन्हा के यहां गए और उन से निवेदन किया कि मेरी लड़की जो विद्यालय से पढ़कर घर वापस आ रही थीं, रास्ते में गायब कर ली गई । माननीय सदस्य श्री पूर्ण सिन्हा जी ने एक पत्र गृह मंत्री जी को लिखा—अगर 24 घन्टे के भीतर नंदिता मजूमदार को बरामद नहीं किया जा सकेगा तो हम इस सवाल को लोक सभा में उठायेंगे । श्री विमल सरकार प्रधान मंत्री जी के यहां भी गए थे । दो दिन बाद यानी ता० 21 को नन्दिता मजूमदार बरामद हुई ।

आप को यह जान कर आश्चर्य होगा—जब श्री विमल सरकार पुलिस मे गए और उन्होंने पुलिस अफसर से निवेदन किया कि यह हमारी लड़की का फोटो है, इस को अखबार मे निकलवा दो और इस की छानबीन करो । तो पुलिस आफिसर ने रिफ्यूज किया इसलिए कि पुलिस आफिसर का एक रिलेटिव इस मामले मे जिम्मेदार था ? यही वजह थी कि लड़की छुपा कर रखी गई थी और जब उन से इस बारे मे कहा गया तो उन्होंने अनसुनी कर दी लेकिन जब माननीय सदस्य ने इस का नोटिस लिया और उन्होंने गृह मंत्री जी को लिखा तब जा कर लड़की बरामद हुई । आप यह जानते है कि आजकल दिल्ली मे क्राइम बढ़ रहे हैं और किसी आदमी की इज्जत महफूज नहीं है । किस की लड़की कहां और कब गायब हो जाए, इस का ठिकाना नही है ।

इस आंतकपूर्ण स्थिति की ओर मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं ।

12.56 hrs.

PUBLIC SECTOR IRON AND STEEL COMPANIES (RESTRUCTURING) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS BILL—*Contd.*

MR. SPEAKER: We take up further Clause-by-Clause consideration of the Public Sector Iron and Steel (Restructuring) and Miscellaneous Provisions Bill.